(b) the sites out of these which are dangerous;

(c) what is being done to protect the surrounding population from any accidents on these abandoned sites; and

(d) how many accidents have taken place on these sites during the last year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d) The information till date has not been sent by the concerned State Governments. On receipt of the information, it will be placed on the Table of the House.

इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण

*187. **श्रीमती सरला माहेश्वरी :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये रूस के साथ कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रूस द्वारा भारत को आधुनिकतम इस्पात तकनीक दिये जाने की संभावनाओं पर भी उस देश के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये कोई बातचीत नहीं हुई है । तथापि, रूसी, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर भाग ले रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इंडो-रसियन फेडरेशन ज्वाइंट कमीशन के उदघाटन-सत्र जो जून, 1994 में हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ लौह तथा अलौह धातुओं के संबंध में कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया । इस दल की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। तथापि, बातचीत के लिये सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है:—

(i) प्रौद्योगिकी सहयोग जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल है ।

(ii) वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों का एक दूसरे के देश में दौरा ।

(iii) अनुसंधान और विकास (आर० एंड डी०) के क्षेत्र में सहयोग ।

अरबी मदरसों को अनुदान दिया जाना

*190. **श्री मोहम्मद मसूद खान :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य से मान्यता-प्राप्त अरबी मदरसों को अनुदान देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या-क्या शर्तें हैं, और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्य से मान्यता प्राप्त अरबी स्कूलों को अनुदान देने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है लेकिन प्राचीन भाषाओं, जिनमें अरबी भी शामिल है, के परिरक्षण और प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान देने के लिए एक योजना है ।

(ख) इस योजना की मुख्य शर्तें निम्नवत हैं :—

(i) अरबी के परिरक्षण और प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(ii) वित्तीय सहायता के लिए सभी अनुरोध राज्यों के माध्यम से भेजे जाए तथापि अखिल भारतीय स्वरूप के संगठनों से अनुदानों के लिए अनुरोध केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

(iii) इन अनुदानों को संस्थाओं की भाषा पढ़ाने के लिए कक्षाएँ आयोजित करने, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण, दुर्लभ पाण्डुलिपियों के प्रकाशन, छात्रवृत्तियों को प्रदान करने, भवनों के निर्माण और मरम्मत, अनुसंधान इत्यादि जैसे लक्ष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(iv) अनुमोदित योजना के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता सामन्यतः कुल व्यय की अधिक से अधिक 75 प्रतिशत तक की सीमा तक सीमित होती है।

(v) अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन का केंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

(vi) लेखों का ठीक ढंग से रख रखाव रखा जाएगा और भारत के नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।

(vii) जिस कार्य के लिए अनुदान स्वीकृति किया गया है उसके बारे में, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/सुझावों का पालन करने के लिए वह सगठन बाध्य होगा ।

(ग) वर्तमान योजना अरबी की प्रोन्नति और परिरक्षण के लक्ष्य को पूरा करती है।

Estimate of Housing Shortage

*191 SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the latest estimates of housing shortage for different income groups in 23 mega cities of India;

(b) whether it is a fact that those shortages are increasing every year;

(c) whether, in view of the inadequacy of the current programmes and policies to arrest the deteriorating conditions, new measures are being contemplated and enforced; and

(d) if so, the details of these measures?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) According to estimates made by the National Building Organisation (NBO) based on 1971 and 1981 Census data, the housing shortage in urban areas as on 1-3-1991 was 10.40 million. The State-wise break-up of the shortage is given in the Statement (see below). NBO has not made city-wise estimates of housing shortage.

(b) According to NBO estimates, the housing shortage has tended to increase from year to year.

(c) and (d) A ntw National Housing Policy has been formulated. It envisages:—

(i) reorientation of the role of public housing agencies from one of builder to that of enabled.

(ii) removal of legal and other constraints inhibiting housing development activities;

(iii) augmentation of the inflow of housing finance through increased Budgetary support and institutional finance.

(iv) involvement of the private sector, cooperatives and non-Governmental organisations in housing development activities;

(v) stepping up of support of developed lands, infrastructure and services;

(vi) promoting cost-effective building material and technology by utilising